

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वर्तनीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
1.	सभी वभागों के अधकारियों एवं कर्मचारियों की कम्प्यूटर साक्षरता सुनिश्चित करने का अभयान चलाया जायेगा।	--	न्यूनतम 300 कर्मचारियों को आई.टी. प्र शक्षण प्रदान करना।	न्यूनतम 300 कर्मचारियों को आई.टी. प्र शक्षण प्रदान करना।	न्यूनतम 300 कर्मचारियों को आई.टी. प्र शक्षण प्रदान करना।	पूर्व से उपलब्ध
			--	--	15 जिलों में क्षेत्रीय आई.टी. प्र शक्षण केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ करना	पूर्व से उपलब्ध
2.	हर वभाग अपना ई-गवर्नेन्स प्लान बनाकर उसे क्रयान्वित करने के लए बजट में रा श सुनिश्चित करायेगा। न्यूनतम 2 प्रतिशत बजट रा श वभाग को ई-गवर्नेन्स पर व्यय करनी होगी।	प्रत्येक वभाग द्वारा ई-गवर्नेन्स प्लान बनाकर कार्यान्वित कया जाएगा ।	यद्यपि पूर्व से प्रावधानित है तथा पुनः निर्देश जारी कये जायेंगे।	--	--	--

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वर्तनीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
3.	ई-गवर्नेन्स को सफल बनाने के लए यूजर चार्जेस का तंत्र स्थापत कया जायेगा।	--	यूजर चार्जेस का तंत्र स्थापत करने हेतु अध्ययन कर सुझाव देने के लए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन	--	यूजर चार्जेस के संबंध में समिति की अनुशंसाओं के आधार पर नवीन दिशानिर्देश जारी करना।	--
4.	ई-टेण्डरिंग, ई-मेजरमेंट, ई-पैमेंट जैसी प्रणालियों को अन्य महत्वपूर्ण वभागों में भी प्रयुक्त करने की कार्यवाही की जावेगी।	सभी सरकारी वभागों के लये निवदायें ऑनलाइन की जायेंगी. सभी वेंडर्स के लये भुगतान ई-पेमेंट प्रणाली के क्रयांवयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कया जायेगा।	न्यूनतम 10 नये वभागों/कार्यालयों को ई-टेण्डरिंग पोर्टल से जोड़ना।	न्यूनतम 10 नये वभागों/कार्यालयों को ई-टेण्डरिंग पोर्टल से जोड़ना।	ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर ई-मेजरमेंट, ई-पैमेंट की व्यवस्था लागू कया जाना।	--

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वर्ततीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
5.	कसानों को खसरा खतौनी की प्रति बिना कसी शुल्क के प्रदान करना।	भू-कर-सम्बन्धी नक्शों का डिजिटাইजेशन और भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों की ऑनलाईन उपलब्धता को सुनिश्चित किया जायेगा।	ई-खसरा परियोजना का पोर्टल भोपाल एवं सीहोर जिले में प्रारम्भ करना।	सफल पायलट उपरान्त ई-खसरा परियोजना का वस्तार नये 10 जिलों में करना।	ई-खसरा परियोजना का वस्तार प्रदेश के सभी 51 जिलों में करना	--
6.	सभी कलेक्टर कार्यालयों एवं तहसील कार्यालयों को जोड़ कर ऑनलाईन इंटीग्रेटेड सस्टम का विकास ताक नागरिकों को उनकी भूमि के अभिलेख ऑनलाईन उपलब्ध हो सके।					
7.	हिन्दी में ऑनलाईन और वेब आधारित स्कूली एवं महा विद्यालयीन शिक्षा।	उत्कृष्ट शिक्षा वदों की विशेषज्ञता का लाभ ब्लॉक स्तर तक पहुँचाने हेतु स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना। एक सुदृढ वर्चुअल क्लास रूम एज्युकेशन प्रोग्राम का क्रयान्वयन।	--	--	समस्त 411 चन्हित विद्यालयों एवं महा विद्यालयों में कनेक्टि वटी स्थापित करना।	पूर्व से उपलब्ध

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वर्तनीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
8.	एनिमेशन, ग्रा फक्स डजाईन, ड्रॉफ्ट्समेनशीप आदि क्षेत्रों में अकाद मर्यों खोली जायेंगी।	घरेलू बीपीओ के लए टियर थ्री शहरों को हब के रूप मे वकसत करना एवं तकनीकी क्षेत्र के मोबाईल एप्लीकेशन, गै मंग, एनीमेशन एवं अना लटिक्स जैसे उभरते कार्यक्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन ता क आई.टी. उद्योगों को तरक्की के नये अवसर प्राप्त हों।	एनीमेशन के क्षेत्र में निजी निवेशकों की कार्यशाला का आयोजन एवं निवेश को इच्छुक कम्पनियों को आई.टी. नीति के तहत आवश्यक सहयोग प्रदान करना।	बीपीओ के लए उपयुक्त सभी जिलों में भूम का आरक्षण एवं आवंटन सूचना प्रौद्यो गकी वभाग के पक्ष में कराना	न्यूनतम 3 टियर थ्री शहरों में बीपीओ के शुभारम्भ के प्रयास करना।	--
9.	देवास, इन्दौर, धार एवं भोपाल जिलों में इलेक्ट्रॉनिक सस्टम डजाईन एवं निर्माण में निवेश को प्रोत्साहन।	देवास, इन्दौर, धार एवं भोपाल जिलों में जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्यो गकी वभाग द्वारा ब्राउन फल्ड क्लस्टर के रूप में अधसू चत कये गये हैं, एवं संशोधत वशेष प्रोत्साहन पैकेज के लए उपयुक्त हैं, में इलेक्ट्रॉनिक सस्टम डजाईन एवं निर्माण में निवेश को प्रोत्साहन।	--	1. भोपाल एवं जबलपुर हेतु भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त करना। 2. इन्दौर एवं ग्वा लयर हेतु भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति लेना।	1. ड्राईंग डजाइन को अंतिम रूप देना 2. बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।	----

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वर्तनीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
10.	प्रदेश में स्थित सभी मंदिरों एवं उनकी भूमियों की जानकारी को सूचीबद्ध कर प्रत्येक जिले की जानकारी वभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराना।	--	--	--	एसएसडीजी परियोजना अंतर्गत धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व वभाग की वेबसाईट लांच करना जिसमें उक्त सुवधा शामिल हो।	पूर्व से उपलब्ध
11.	मध्यप्रदेश में न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोर्ट ऑफ टूमारो की अवधारणा पर कार्य करना।	त्वरित वचारण एवं न्याय के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोर्ट सहित राज्य के सभी न्यायालयों को ऑनलाईन केस फाई लंग, पडत और अपराधी की वडयो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये पेशी, केसों की ऑनलाईन ट्रैकंग के साथ कम्प्यूटरीकृत कया जायेगा और निर्णयों की प्रमाणत प्रतियों उपलब्ध होंगी।	--	महधक्ता कार्यालय के कम्प्यूटराईजेशन हेतु एजेन्सी का निर्धारण कार्य पूर्ण करना।	नेशनल लॉ यूनिवर्सटी के माध्यम से परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देने में वध वभाग को सहयोग।	पूर्व से उपलब्ध

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वर्तीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
12.	--	सार्वजनिक सेवाओं के प्रदाय पर नागरिकों की प्रति क्रयाओं को ऑनलाइन और एस एम एस आधारित सस्टम के माध्यम से सक्रय रूप से प्रावधानित कया जायेगा।	---	एमपीऑनलाईन पोर्टल, लोक सेवा पोर्टल एवं स्टेट पोर्टल पर इस सस्टम को स्था पत करना	--	पूर्व से उपलब्ध
13.	--	एक समेकत पोर्टल - स्टेट सर्वस डलवरी गेटवे के माध्यम से व भन्न सार्वजनिक सेवायें (जिनमें ई-डस्ट्रिक्ट, पब्लिक सर्वस गारंटी एक्ट आदि के तहत प्रस्तावत सेवायें शामिल हैं) जैसे कल्याण योजना भुगतान को ऑनलाइन प्रस्तावत कया जायेगा।	--	एमपीऑनलाईन पोर्टल, लोक सेवा पोर्टल एवं स्टेट पोर्टल के इंटीग्रेशन की रणनीति सक्षम समति से अनुमोदन कराना	नवीन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क लागू करना।	पूर्व से उपलब्ध
14.	---	नागरिकों को सेवाओं के वतरण हेतु समर्पत नम्बरों से मोबाइल फोनों के द्वारा कहीं भी, कभी भी पहुँच उपलब्ध करायी जायेगी, और		सभी 51 जिलों की वेबसाइट्स को गार्डड लाईन	स्टेट एप्प स्टोर का वकास कर न्यूनतम 3	पूर्व से उपलब्ध

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वत्तीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
		साथ ही स्मार्ट फोन/ इंटरनेट-ब्राउजर-अनुकूल सरकारी वेबसाइट भी बनायी जायेंगी।		अनुरूप वक सत करने हेतु एनआईसी के सहयोग से कार्य प्रारम्भ करना।	मोबाईल आधारित सेवाएँ प्रारम्भ करना।	
15.	---	प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को पहचानने के लये सभी वभाग एक “आउटकम ड लवरी फ्रेमवर्क” अपनायेंगे और प्रति वर्ष औसत परिणाम प्राप्त कये जायेंगे। लक्ष्यों को वत्तीय वर्ष के पहले माह में ही निर्धारित कर वभाग की वेबसाइट पर प्रका शत कया जायेगा।	--	वभाग का आउटकम ड लवरी फ्रेमवर्क तैयार कर वभाग की वेबसाइट पर प्रका शत कया जाना।	--	--
16.	---	पेपरलेस ऑ फस वातावरण को बढावा दिया जायेगा और सरकारी कार्यालयों के अन्दर दक्षता सुधारने हेतु प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की प्र क्रया को अपनाया जायेगा	---	--	ई-ऑ फस परियोजना को पूर्व चयनित 8 कार्यालयों में	पूर्व से उपलब्ध

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वर्तनीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
17.	---	शासकीय सेवा में सुधार हेतु फाइल प्रबन्धन, ज्ञान प्रबन्धन, कर्मचारी जानकारी, और सूचना सेवायें ई-ऑफिस प्रणाली के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेंगी।			पूर्णतः प्रारम्भ करना	
18.	---	संसाधनों के समयावध आधारित और प्रभावी सदुपयोग हेतु 50 करोड से अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सस्टम को कार्यावत कया जायेगा।	राज्य शासन स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल की स्थापना	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तथा राज्य शासन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रथम विशेष ट्रेनिंग का आयोजन।	पूर्व से उपलब्ध
19.	---	सम्पत्ति के उपयोग को उपलब्ध कराने के लिये एक समर्पित GIS लैब की स्थापना की जायेगी (जैसे कहाँ और कब अस्पताल उपकरण जैसे संसाधनों को लगाना प्रयोग के आधार पर वाहन) और स्थान के आधार पर नागरिक सेवायें प्रदान की जायेंगी।		जीआईएस लैब हेतु मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना स्थापित करना।	न्यूनतम एक वभाग कार्यालय में जीआईएस आधारित Decision support system प्रारम्भ करना।	पूर्व से उपलब्ध
20.	---	रैड डाटा और ई-गवर्नेंस आवेदन पत्र बांटने और State Wide Area Network तथा M.P. Government Cloud Computing के द्वारा परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से कार्य करने के	GI Cloud की RFP जारी करना।	--	हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी बढ़ाकर न्यूनतम 3	पूर्व से उपलब्ध

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वर्तीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
		माध्यम से ICT वातावरण को बढ़ावा दिया जायेगा			हजार कार्यालयों तक पहुँचाना।	
21.	---	व भन्न डाटा बेसों (जैसे आधार, डी एल नम्बर, स्कीम बेनेफिशियरी रेजिस्ट्रेशन नम्बर आदि) के ID नम्बरों पर आधारित वभागों के डाटा बेसों को जोड़ कर एक कॉमन डाटा रिपोजिटरी स्थापित की जायेगी।	डेटा बेसेस के इंटीग्रेशन हेतु रणनीति तैयार करना।	स्टेट डेटा सेन्टर में स्टेट रेसिडेंट डेटा हब की स्थापना	स्टेट रेसिडेंट डेटा हब में न्यूनतम 3 वभागों का डेटाबेस इंटीग्रेट करना।	--
22.	---	डाटा को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में सक्रय रूप से उपलब्ध कराने हेतु मुक्त सरकारी सहभागिता की मुक्त डाटा पॉलसी और ढाँचे का निर्माण।	ओपन डेटा पॉलसी का मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त जारी करना।	--	--	--
23.	---	महिलाओं एवं बालकाओं से संबंधित सभी कार्यक्रमों, योजनाओं कानूनों नियमों आदि की जानकारी प्रदान करने हेतु महिला पोर्टल की स्थापना।	--	--	एसएसडीजी परियोजना द्वारा महिला एवं बाल विकास वभाग	--

क्रमांक	संकल्प -2013	दृष्टिपत्र-2018	लक्ष्य			वर्ततीय संसाधन
			जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	
					को सहयोग प्रदान करना।	
24.	---	सभी नगर निगमों में नागरिक सेवा केन्द्रों की स्थापना।	--	--	एमपीऑनलाईन कयोस्कों का वस्तार	--